

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम औसिया

जालमसिंह बनाम लक्ष्मणसिंह वगैरा

किरम मुकदमा विविधि प्रार्थना पत्र नम्बर 1. / 2020

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज

नम्बर व तारीख
अदालत जो इस हुकम
की तामिल में जारी हुए

तारीख
हुकम
30.12.2020


प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को दिलाई गई । अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाब पेश किया जिसकी नकल प्रार्थी के अधिवक्ता को दिलाई गई । दोनो अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । हल्का पटवारी व तहसीलदार की मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे सामिल मिसल की गई । दोनो अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई । पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । प्रार्थी का कथन है कि ग्राम डाबडी के खसरा नम्बर 385/373 रकबा 30 बीघा 9 बीस्वा भूमि प्रार्थी के खातेदारी की आई हुई है जिसमे पड़ौसी खातेदार द्वारा नाजायज अतिक्रमण करने का प्रयास करने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण लक्ष्मणसिंह वगैरा के खिलाफ सन् 2007 में एक राजस्व वाद पेश किया जो अदालत हाजा में विचाराधीन है तथा उक्त वाद के टी.आई.प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के विरुद्ध मोके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्टे आदेश जारी हो रखा है । प्रार्थी उक्त भूमि में अपनी रिहायसी ढाणी में पानी व बिजली का कनेक्शन लेने हेतु फाईले जमा करवाई जिनमें मांग पत्र प्राप्त होने पर सरकार ने मांग पत्र की राशि जमा करवाई जा चुकी है लेकिन उक्त विभागो द्वारा यथास्थिति के आदेश के कारण प्रार्थी को पानी व विधुत कनेक्शन नहीं दे रहे है । पानी व विधुत का सम्बन्ध लेना प्रार्थी का सवैधानिक भूल भूत अधिकार है इसलिए प्रार्थी को पानी व विधुत कनेक्शन करने की अनुमति प्रदान करावे ।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में यह बताया कि दिनांक 10.3.2008 को न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया हुआ है तथा भोतिक संरचना में परिवर्तन नहीं करने का आदेश है इसके अलावा अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में यह भी बताया कि पूर्व में दिनांक 15.7.2016 को धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र विधुत व पानी का कनेक्शन लेने बाबत इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है जिसके खिलाफ प्रार्थी ने कोई अपील पेश नहीं की है तथा पुनः दुसरा प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. के तहत पोषणीय नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

हमने दोनो अधिवक्ताओ की बहस पर गौर किया ,हल्का पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया । मानव अधिकारों के तहत हवा, पानी, प्रकाश, विधुत की रोशनी अति आवश्यक प्रकृति में आती है तथा मानव जीवन के लिए एवं आज के वैज्ञानिक युग में मोबाईल फोन, टी.वी. आदि चलाने के

अदालत मुकाम औसिया

लिए एवं बाल बच्चों की पढाई के लिए विधुत कनेक्शन का होना अति आवश्यक है तथा पानी मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है इसलिए मामले के हालात व परिस्थितियों को मध्य नजर रखने हुए इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी किये गये स्टे आदेश में पानी व विधुत सम्बन्ध प्रार्थी को नियमानुसार दिये जाने में छुट प्रदान की जाती है तथा प्रार्थी उक्त पानी व विधुत सम्बन्ध के आधार पर विचाराधीन मूल वाद में बादी अपने कब्जे अधिकार व अधिपत्य के बारे में साक्ष्य सबूत के आधार पर कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा तथा उक्त पानी व विधुत सम्बन्ध तथा यह आदेश पूर्ण रूप से मूल वाद के निर्णय के अधिन रहेंगे । इस प्रकार से प्रार्थी को उक्त भूमि में पानी व विधुत सम्बन्ध देने की छुट प्रदान की जाती है । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर मूल पत्रावली के सलंग्न की जावे


[Signature]